सदन को मिलकर इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी धर्म के खिलाफ इस प्रकार कार्यवाही करना तुरन्त बंद होना चाहिए।

RE. ATTACK ON JOURNALISTS IN KASHI

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि आज वाराणसी में बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है और वह आग इसलिए लगी हुई है कि वहां पर वर्षों से काशी पत्रकार संघ जो वहां का सबसे पुराना पत्रकार संघ है, जिससे पराड़कर जी का संबंध रहा है, उस नगरी में पत्रकारों के ऊपर बहुत जबरदस्त आक्रमण किया गया है और वह आक्रमण इसलिए किया गया है कि वहां के पत्रकार काशी पत्रकार संघ के तत्वावधान में एक व्यक्ति द्वारा जो विधायक भी है, वकील भी हैं .....

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : किस दल के हैं ?

श्री राम नरेश यादव : वह बी.जे.पी. के हैं, मैं उसी बात पर आ रहा था .... (व्यवधान) उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसी दुर्व्यवहार के बारे में पत्रकार जा रहे थे जिला हेडक्वार्टर पर, जिला मजिस्ट्रेट के सामने धरना देने के लिए और यह जानकारी हो गई इसी बीच में तो उस विधायक ने, उस वकील ने अपने साथियों के साथ बहुत जबरदस्त रूप से आक्रमण कर दिया जिसमें कई पत्रकार घायल हो गए तब से स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। और पत्रकार मौन जलूस निकाल रहे हैं यह आग गाजीपुर पुर्वांचल में सब जगहों पर फैल रही है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है मुझे तो यह भी डर लगता है कि हो सकता है बढ़ते बढ़ते यह देशव्यापी न हो जाए और यह पत्रकार संघ उसको और आगे बढ़ाने का काम न करें जो शान्ति और व्यवस्था का बहुत बड़ा कारण बनेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध चाहता हूं कि सरकार समय रहते उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे और जल्दी से जल्दी जिन लोगों का इस में हाथ है, उन को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

महोदया, आप जानती हैं कि पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार अनुचित है, पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी है। उन के ऊपर इस तरह का आघात इस तरह का आक्रमण न होने पाए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) महोदया, मैं उस दिन बनारस में था और मुझे खेद है कि यह घटना हुई। मैं स्वयं उस एम. एल. ए. से मिला हूं। उन को अपनी करनी पर पछतावा है अब गलती किस की थी पत्रकारों की थी या इन की थी, इस बात में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अपने दल की ओर से मैं खेद प्रकट करता हूं। इस प्रकार की घटना बहुत अनुचित है, नहीं होनी चाहिए।

महोदया, जिस दिन मैं आडवाणी जी से मिलने गया उस दिन मैं बनारस में था अपने सहयोगी को मैंने कहा और मैं समझता हूं पत्रकार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है हम कभी उन का अपमान नहीं करना चाहते।

श्री राम नरेश यादव : महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं ..... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : No, Mr. Yadav, no more. You finished. You had your say. Now, I just want to request. Before I take up Special Mentions, we will finish some legislative business. Now the Railway Minister will introduce a Bill.

THE RAILWAYS (AMENDMENT) BILL, 1993

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF) : Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill

to amend the Railways Act, 1989 and the Railway Claims Tribunal Act, 1987.

The question was proposed.

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA (Uttar Pradesh) : Madam, I have got an objection. I have gone through the provisions of the Bill. Recently, when an accident took place near Pune where a bus carrying school children collided with a train at some railway level crossing, the Railway Minister has pointed out that compensation will be paid to them as a special case. But those provisions have not been included in the Bill.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF : I have already made a commitment to the House that I am going to take it up in the Cabinet.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : Now, put the motion to vote.

The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Railways Act, 1989, and the Railway Claims Tribunal Act, 1987.

The motion was adopted.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF Madam, I introduce the Bill.

SPECIAL MENTION

Need for Granting Special Category Status to Pondicherry

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Madam Vice-Chairman, I thank you for giving me this opportunity to raise an issue relating to my Union Territory of Pondicherry. We have been making a claim to the Government of India that Pondicherry should be given a statehood. The reason is, we have a legislature, we have an Administrator for the State and we have elected representatives, but the problem is that there is a lack of interest .... (*Interruptions*) ....

SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA (Gujarat) : Madam, my name was to be called first.... (*interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I will tell the Members why I called Mr. Narayanasamy first. He is now going to preside over; that is why I have called him. He has to come to the Chair again..... (*Interruptions*).....

AN HON. MEMBER : Is he in a hurry to go ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : No, no. There is a certain procedure involved. That is why I called him. I will call Mr. Shukla next.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : Madam, why are you so eager to vacate it ? This has to be explained.

SHRI V. NARAYANASAMY : Normally, the Administrator has to go by the aid and advice of the Council of Ministers. If there is a clash of interests on some matter and the administrator finally decides against the advice of the Council of Ministers ultimately the matter has to be referred to the Home Ministry. Though we have elected representatives and a Council of Ministers, we have to be at the mercy of the Government of India in financial matters also. In service matters it is pathetic that even for creation of posts or for promotion of officers we have to send the file to the Home Ministry and the Home Ministry keeps the file with it for one or two years and then the response is not received from them. Every time we have to come to the Home Ministry and explain to them and they will return the file for a small clarification and in that process several years elapse. Not only that; there is also a very peculiar aspect to be mentioned. The National Calamity Fund has been created on the recommendation of the Ninth Finance Commission. Whenever there is a calamity in my Union Territory of Pondicherry, our Territory has not been allowed to get funds directly. Only the States are getting funds from the Government of India. As far as